



67

न्यायालय - श्रीमान् राजस्व मण्डल न्यायालय ४ मु १० ४

मथुरा प्रसाद तनय नाथूराम बाम्हण

श्री राजीव शर्मा  
5/9/16

न्यायालय नहर बुजुर्ग, तहसिल पलेरा जिला टोकमगढ़, म०प्र० - - निगरानीकर्ता/  
आवेदक

॥ विच्छ ॥

निं 3032-I/16

श्रीमान् दास तनय प्रागो नाथित

निवासी नहर बुजुर्ग तहसिल पलेरा जिला टोकमगढ़ म०प्र० - - उत्तरवादी

निगरानी प्र० क्र०:

निगरानी/आवेदन अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० राजस्व संहिता -1959 :-

निगरानीकर्ता/आवेदक को ओर से निम्न प्रार्थना है :-

यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अद्विभागीय अधिकारी जतारा के प्रकरण क्रं. 112/अपोल/2015-2016 में पारित आदेश दिनांक 12/08/2016 से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

-: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

1. यह कि, निगरानीकर्ता/आवेदक को न्यायालय श्रीमान् तहसिलदार पलेरा के प्रकरण क्रमांक "64/अ-19 अ-वर्ष 1993-94 के आदेश दि. 23/09/1994 के अनुसार मौजा स्थित नहर बुजुर्ग खतरा नंबर 470 रकबा 0.530 हे. एवं खतरा नंबर 465/1 रकबा 0.057 हे. कुल रकबा 0.597 हे. प्राप्त हुआ था। न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर टोकमगढ़ का प्र. क्रं. 12/स्व. निग./13-14 आदेश दिनांक 06/04/15 स्टेटिंग आर्डर है जो कि आज दिनांक तक पथावत है जो कि निरस्त नहीं हुआ है।

2. यह कि, तहसिलदार पलेरा जिला टोकमगढ़ को विचारण न्यायालय में उत्तरवादी द्वारा इत आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम मौजानहरबुजुर्ग में स्थित खतरा नंबर 470 रकबा 0.533 हे. भूमि पर निगरानीकर्ता द्वारा पटवारों से मिलकर फर्जी प्रविष्टि कराकर अपने नाम पर उक्त भूमि राजस्व रिकार्डों में दर्ज करा ली है उसका नाम काटा जावे व उक्त विवादित भूमि खतरा न. 470 रकबा 0.533 हे० पर म.प्र. शासन दर्ज किया जावे।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने हितबद्ध पक्षकार न होते हुये भी उत्तरवादी का आवेदन को स्वीकार कर अपना आलोच्य आदेश दिया है जो पारित आदेश दिनांक 12/08/2016 के विच्छ निगरानीकर्ता/आवेदक यह निगरानी श्रीमान् जो के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

..2.

B/S



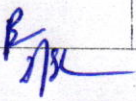
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

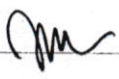
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3032-एक / 2016

जिला-टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिषेक आदि के हस्ताक्षर
4.10.16	<p>यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला- टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 112/अपील /2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12-08-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है.</p> <p>2. प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है तहसीलदार पलेरा जिला-टीकमगढ़ के समक्ष अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मौजालहर बुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 470 रकबा 0.533 हे0 पर आवेदक द्वारा पटवारी से मिलकर फर्जी प्रविष्टि कराने तथा उक्त प्रविष्टि को विलोपित करने तथा भूमि को शासकीय अंकित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया. जिसे तहसीलदार द्वारा 'निरस्त किया गया . तहसील आदेश के विरुद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो उनके द्वारा स्वीकार की गयी . अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध यह निगरानी मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है.</p> <p>3. आवेदक अभिषेक द्वारा अपने तर्कों में पुनरीक्षण आवेदन पत्रों में वर्णित तर्कों पर जोर देते हुए पुनरीक्षण आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी.</p> <p>4. आवेदक अभिषेक के तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया. अवलोकन करने से मेरे समक्ष प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार था अथवा उसके कोई हित प्रभावित हुए हैं. क्या तहसील के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य था. तथा क्या तहसील न्यायालय को वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन आदेश के होते हुए कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त था. तथा क्या आवेदक के नाम की प्रविष्टि फर्जी थी.</p> <p>उपरोक्त प्रश्नों में प्रथम प्रश्न की क्या अनावेदक को तहसील न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने का अधिकार था. तथा क्या उसके कोई हित प्रभावित हुए</p>	<p>वि</p>







निगरानी प्रकरण क्रमांक 3032-एक//2016 जिला-टीकमगढ़

है प्रकरण के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि उसके द्वारा तहसील न्यायालय अथवा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह प्रमाणित हो कि वह एक हितबद्ध पक्षकार है तथा उसके कोई हित किसी प्रकार से प्रभावित हुए हैं। तहसील न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया था। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गयी थी उसे स्वीकार करने हेतु जो आधार उनके द्वारा लिये गये हैं वे उचित नहीं पाता हूँ क्योंकि जब कलेक्टर द्वारा 12/स्व0निग0/2013-14 में आदेश दिनांक 6-4-2014 को स्थगन आदेश दिया गया है वह निरन्तर है तब ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं है। तहसीलदार पलेरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/अ-19/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 23-09-1994 द्वारा आवेदक के हित में पट्टा दिया गया था तब ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में की गयी प्रविष्टि को अवैध नहीं माना जा सकता है। प्रकरण की नस्थी उपलब्ध होने अथवा न होने के आधार पर कार्रवाई को फर्जी नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार अथवा निर्णय किया जाना उनके आदेश से परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को न्यायोचित नहीं पाता हूँ इस कारण से उपरोक्त आदेश निरस्त किया जाता है। तथा तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है। तदनुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

R  
1/12

  
सदस्य